150
YEARS OF
CELEBRATING
THE MAHATMA

सत्यमेव जयते

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

जन connect

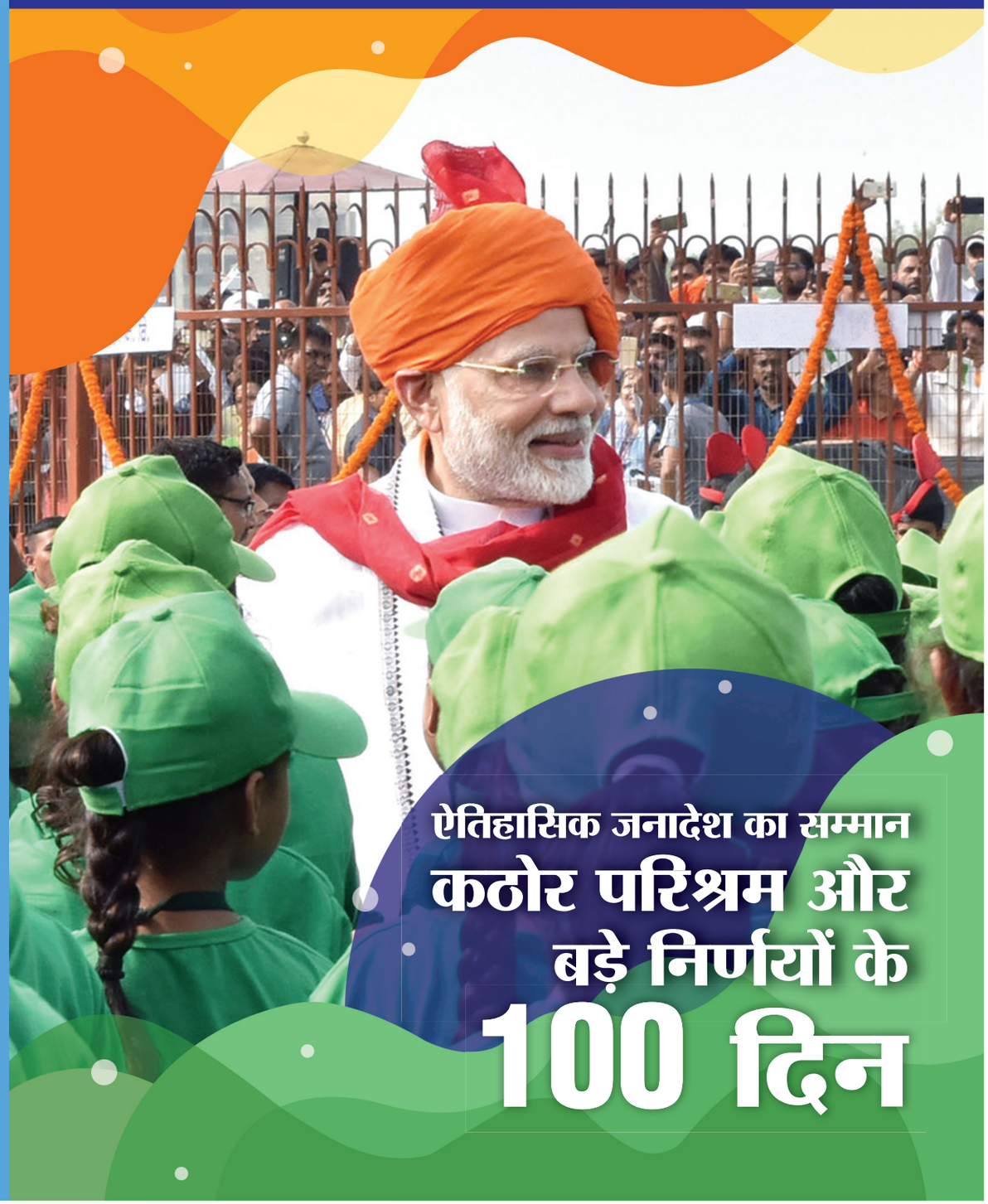

ऐतिहासिक जनादेश का सम्मान

कठोर परिश्रम और बड़े निर्णयों के 100 दिन

ऐतिहासिक निर्णय : जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में लाया गया

ऐतिहासिक निर्णय : जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में लाया गया

मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटा दिया है। संविधान के अनुच्छेद 35ए को निरस्त कर दिया गया है।

- जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के समतुल्य कर दिया गया है।
- भारतीय संविधान के सभी प्रावधान अब से जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होंगे।
- निजी निवेश की अनुमति देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- केन्द्र शासित प्रदेशमें सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़े कानून जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होंगे।
- समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत 10% कोटे का प्रावधान जम्मू-कश्मीर में भी रोजगारों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा।

जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम, 2019

- जम्मू और कश्मीर अब विधानसभा के साथ एक केन्द्र शासित प्रदेश होगा।
- लंबे समय से देखे जा रहे अपने सपने को साकार कर लद्दाख अब एक केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा। हालांकि, वहां कोई विधानसभा नहीं होगी।

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019

- अधिनियम के पारित हो जाने के साथ ही नियंत्रण रेखा (एलओसी) के निकट रहने वाले लोगों के लिए सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध 3% आरक्षण अब से जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के समीप रहने वाले लोगों को भी मिलेगा।

बड़े आर्थिक सुधार 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर

घोषणापत्र के वादों को पूरा करना

- मोदी सरकार ने भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो कैबिनेट समितियों का गठन किया है जो क्रमशः ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझाएंगी।
- दोनों ही पैनलों यथा निवेश एवं विकास पैनल और रोजगार एवं कौशल विकास पैनल के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधारों पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने की भी घोषणा की है। पैनल में कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। यह पैनल सुधारों के लिए आवश्यक विधायी बदलावों पर गौर करेगा।

hindustantimes

नौकरियों से लेकर खेती और इन्फ्रास्ट्रक्चर तक, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित

July 22, 2019

बैंकों का विलय

हिन्दुस्तान

10 बैंक मिलाकर चार बैंक बनेंगे

बड़े फैसले

- 250 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज पर सरकार की सीधी नजर रहेगी
- 10 बैंकों को मजबूत करने के लिए 52,250 करोड़ दिए जाएंगे
- भगोड़ों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई और तेज की जाएगी
- एनबीएफसी को अतिरिक्त 30 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे

पहले उठाए कदम

- रेपो रेट में कटौती को ईएमआई से जोड़ने की घोषणा, कैपिटल गेन्स पर टैक्स सरचार्ज वापस
- नकद प्रवाह बढ़ाने के लिए पांच लाख करोड़ देंगे, स्टार्टअप्स पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा
- सार्वजनिक बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये का पैकेज मिलेगा

- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बना दिए गए हैं। इससे भारत में दूसरे सबसे बड़े, चौथे सबसे बड़े, पांचवे सबसे बड़े और सातवें सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) का सृजन हुआ है।
- इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या अब घटकर 12 रह गई है, जबकि वर्ष 2017 में 27 पीएसबी थे।
- बैंकों के विलय से उनका परिचालन सुगम हो जाएगा, कर्ज देने की लागत घट जाएगी, लाभप्रदता बढ़ जाएगी, और अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी।
- विलय से बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी, बैंक ज्यादा जोखिम उठा सकेंगे, बाजारों से संसाधन जुटाने की क्षमता बेहतर हो जाएगी, देश भर में मजबूत मौजूदगी दर्ज होगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के जरिए अतिरिक्त ऋण देना

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे; अग्रिम और अतिरिक्त उधारी एवं तरलता 5 लाख करोड़ रुपये की होगी; कंपनियां, रिटेल या छोटे ऋण लेने वाले, एमएसएमई, छोटे व्यापारी और अन्य लोग लाभान्वित होंगे।

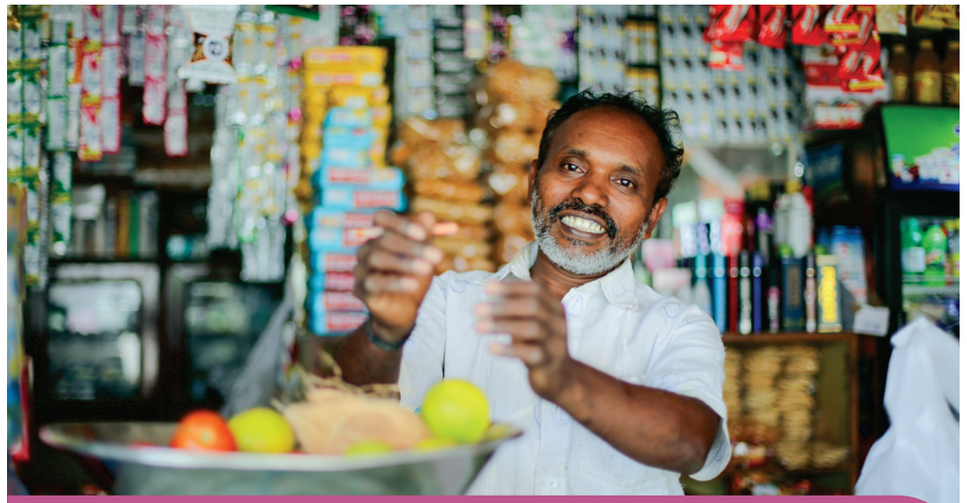

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को सहायता

- राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से एचएफसी 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता सहायता, यह आंकड़ा बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये।

रेपो रेट को ब्याज दर से जोड़ना- आवास ऋण, वाहन ऋण इत्यादि की ईएमआई में कमी

- रेपो रेट को सीधे ब्याज दर से जोड़ कर रिटेल या छोटे ऋणों और कार्यशील पूंजी ऋणों की ईएमआई घटा दी गई है।
- उद्योग जगत के लिए कार्यशील पूंजी ऋण भी सस्ते हो जाएंगे।

बैंक ब्याज दर को शीघ्र कम करेंगे

- बैंक एमसीएलआर में कमी के जरिए रेपो रेट में कटौती का लाभ देंगे, सभी उधारकर्ता लाभान्वित होंगे।

ढांचागत ऋण

- दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाने का प्रस्ताव है, जिससे बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं के लिए ज्यादा ऋण मिलना संभव होगा। इससे इन परियोजनाओं के लिए ऋण प्रवाह बढ़ जाएगा।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा

- ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने अभी से लेकर मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले सभी वाहनों पर स्वीकार्य मूल्यह्रास को बढ़ाकर 30% कर दिया है।
- सरकारी विभागों द्वारा नए वाहनों की खरीद पर पाबंदी हटा दी गई है।
- 31.3.2020 तक खरीदे जाने वाले बीएस IV वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि तक चलाए जा सकेंगे।
- मोदी सरकार निर्यात हेतु बैटरियों सहित सहायक मशीनरी/कलपुर्जों के विकास के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं पर फोकस करती है।
- ई-मोबिलिटी को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।

कारोबार में सुगमता

सीएसआर का उल्लंघन

- इसे दीवानी मामला माना जाएगा।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं की समीक्षा करेगा।
- सरकार ने कंपनियों को अपने सीएसआर दायित्वों को पूरा करने हेतु वर्तमान में जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यथोचित समय दिया है।

कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

- उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद आयकर अधिकारियों के सभी नोटिस एवं समन केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली द्वारा विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या के साथ जारी किए जाएंगे।
- 1 अक्टूबर, 2019 से सभी नोटिसों का निस्तारण, जवाब देने की तारीख से तीन माह के भीतर किया जाएगा।

दीर्घकालिक/अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर पर बढ़े हुए सरचार्ज से राहत

- पूंजी बाजारों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार ने दीर्घकालिक/अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर पर बढ़े हुए अधिभार (सरचार्ज) को वापस ले लिया है।

ग्राहकों को आसानी

- उत्पीड़न को कम करने और अधिक दक्षता लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अब ऋण अदायगी समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर ऋण दस्तावेजों को वापस करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम से वे उधारकर्ता या कर्जदार लाभान्वित होंगे जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति जिससे रखी है।
- ग्राहकों द्वारा ऋण आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की गई - पारदर्शिता बढ़ेगी, उत्पीड़न में कमी आएगी, और आवेदनों के निस्तारण में लगने वाला समय घटेगा।

एमएसएमई

- एमएसएमई के बकाया सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- बेहतर पारदर्शी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति से एमएसएमई और रिटेल या छोटे ऋण लेने वालों की बकाया रकम के मामले निपटाने में आसानी होगी।
- एकल परिभाषा की ओर अग्रसर होने के लिए एमएसएमई अधिनियम में संशोधन करने पर विचार किया जाएगा।

स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा

- स्टार्ट-अप्स और उनके निवेशकों के लिए एंजल टैक्स प्रावधानों को वापस लिया गया।
- स्टार्ट-अप्स की समस्याओं के समाधान हेतु स्टार्ट-अप्स के लिए समर्पित सेल या प्रकोष्ठ।
- 25 करोड़ रुपये तक के कारोबार (टर्नओवर) वाले छोटे स्टार्ट-अप्स को वादे के अनुरूप कर अवकाश आगे भी जारी रहेगा, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट किया गया है। इसमें किसी भी पात्र स्टार्ट-अप के गठन के वर्ष से लेकर अगले 7 वर्षों में से 3 वर्षों तक उसकी आय के 100 प्रतिशत की कटौती का प्रावधान किया गया है।

कराधान - करदाताओं के लिए आसान जिंदगी - आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क

- मोदी सरकार ने करदाताओं को आसानी और सहूलियत हेतु आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 'पैन कार्ड' और 'आधार' की परस्पर अदला-बदली की अनुमति दे दी है।
- आयकर रिटर्न के पहले से ही भरे हुए फॉर्म
- विजयदशमी 2019 से करदाताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ही जांच (स्क्रूटनी)।
- जीएसटी की रिफंड प्रक्रिया सरल की गई।
- करदाताओं से जुड़े मामले निपटाने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण।

श्रम कानून

- ईएसआईसी में अंशदान 6.5% से घटकर 4%।
- भर्ती में लचीलेपन के लिए निश्चित अवधि वाला रोजगार।
- वेब-आधारित और क्षेत्राधिकार-मुक्त निरीक्षण।
- निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर अपलोड कर दी जाएगी।
- अपराधों को संयुक्त करना (कंपाउंडिंग)।
- स्टार्ट-अप्स के लिए स्व-प्रमाणन - 6 श्रम कानून।

पर्यावरणीय मंजूरी

- एमएसएमई के लिए एकल वायु और जल मंजूरी।
- एमएसएमई द्वारा किसी कारखाने की स्थापना के लिए एकल सहमति।

कॉरपोरेट मामले

- अब किसी कंपनी का गठन करने में सिर्फ एक दिन लगता है - नाम पंजीकरण या आरक्षण और गठन के लिए केंद्रीय पंजीयन केंद्र।
- एकीकृत गठन फॉर्म।
- 16 अपराध धाराओं को केवल मौद्रिक दंड में बदलना।
- विलय और अधिग्रहण के लिए त्वरित एवं आसान अनुमोदन।
- भिन्न वोटिंग अधिकारों के लिए प्रावधानों में संशोधन।
- कंपनी अधिनियम के तहत 14,000 से भी अधिक अभियोगों या मुकदमों को वापस लेना।

आईबीसी में संशोधन, इसे और भी मजबूत करना इसका उद्देश्य

- दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में कई संशोधनों को मंजूरी दी गई है।
- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में लाए गए एनपीए मामलों के लिए समाधान अवधि 330 दिन तय की गई है; जिसमें कानूनी चुनौतियों में लगने वाला समय भी शामिल है।

एनबीएफसी द्वारा बैंक केवाईसी का उपयोग

- बार-बार होने वाली प्रक्रियाओं से बचने के लिए एनबीएफसी को 'आधार' प्रमाणित बैंक केवाईसी का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

भारत में बॉन्ड बाजारों को मजबूत बनाना

- दीर्घकालिक वित्त तक पहुंच बढ़ाना।
- आरबीआई और सेबी के परामर्श से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाजारों का विकास।
- वित्त मंत्रालय बांडों के घरेलू बाजार को बेहतर बनाने के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम करेगा।
- डिबेंचर विमोचन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर नियम) 2014 में संशोधन किया गया।

वैश्विक बाजारों में भारतीय कंपनियों की पहुंच

- डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014 को सेबी द्वारा जल्द ही शुरू किए जाने की उम्मीद है। यह एडीआर/जीडीआर के जरिए विदेशी फंडों तक भारतीय कंपनियों की पहुंच बढ़ाएगी।

घरेलू छोटे निवेशकों के लिए 'आधार' से संबंधित केवाईसी का उपयोग

- घरेलू छोटे या रिटेल निवेशकों की बाजार पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से डीमैट खाता खोलने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए 'आधार' से संबंधित केवाईसी को अनुमति दी जाएगी।

विदेशी निवेशकों और एफपीआई के लिए सरल केवाईसी

- सरल केवाईसी प्रक्रिया से एफपीआई सहित विदेशी निवेशकों की बाजार पहुंच बढ़ जाएगी।

ऑफशोर रुपया बाजार

- ऑफशोर रुपया बाजार को घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों में लाया जाएगा और जीआईएफटी आईएफएससी में अमेरिकी डॉलर- भारतीय रुपया डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग की अनुमति दी जाएगी।

5 वर्षों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये

- 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर-मंत्रालय कार्य बल का गठन किया गया।
  इस पहल से विकास को नई गति मिलने और नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है।

कॉरपोरेट टैक्स में कमी

- 400 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार (टर्नओवर) वाली सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
- इससे 99.3 प्रतिशत कंपनियां लाभान्वित होंगी।

विभिन्न सेक्टरों पर एफडीआई नीति की समीक्षा को मंजूरी

- एफडीआई नीति में बदलावों से भारत और भी अधिक आकर्षक एफडीआई गंतव्य बन जाएगा जिससे निवेश, रोजगार सृजन और विकास की गति तेज होगी।
- कोयला खनन के लिए स्वतः रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई एक दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार सृजित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करेगा।
- अनुबंध पर विनिर्माण में स्वतः रूट के तहत अब एफडीआई को अनुमति मिलने से 'मेक इन इंडिया' के उद्देश्य को काफी बढ़ावा मिलेगा।
- प्रिंट मीडिया की तर्ज पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचारों एवं समसामयिक मामलों की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग के लिए अब सरकारी रूट के तहत 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।
- मौजूदा एफडीआई नीति में यह प्रावधान है कि एसबीआरटी इकाई में 51 प्रतिशत से अधिक एफडीआई होने पर वस्तुओं के कुल मूल्य का 30 प्रतिशत भारत से ही खरीदना पड़ेगा। अब सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (एसबीआरटी) में एफडीआई के लिए स्थानीय यानी भारतीय बाजार से खरीदने (सोर्सिंग) के मानदंडों को आसान बना दिया गया है। इससे एसबीआरटी इकाईयों में अधिक लचीलापन आएगा और परिचालन में आसानी होगी। इसके अलावा, किसी आधार वर्ष (बेस ईयर) में ज्यादा निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए समान अवसर सृजित होंगे।

कंपनी संशोधन अधिनियम, 2019

- संशोधित अधिनियम 'कारोबार में सुगमता' और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एवं विशेष अदालतों की सहूलियत को बढ़ावा देता है। अधिनियम कंपनियों द्वारा उल्लंघन के गंभीर मामलों और अपेक्षाकृत अधिक अनुपालन सुनिश्चित किए जाने पर फोकस है।

विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019

- एसईजेड (संशोधन) अधिनियम से कोई भी कंपनी एसईजेड में ट्रस्ट सहित अपनी यूनिट लगाने में समर्थ हो सकेगी। इससे निवेश को प्रोत्साहन देने और निर्यात तथा रोजगार के नये अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी।
- इस साल के आरंभ में अध्यादेश जारी होने के बाद से लेकर अब तक 1.1 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव है।

व्यापारियों की - काफी अर्से से लंबित मांग पूरी हुई

- व्यापारियों और कर्मचारियों के रोजमर्रा के कारोबारी जीवन में उनके समक्ष आने वाली समस्याओं और मसलों को समझने तथा उनके कल्याण के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई।

व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद तथा व्यापार बोर्ड का विलय

- निर्यात से संबंधित चिंताओं को दूर करने और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए साझा मंच

हवाई अड्ड़ों को पट्टे पर देने के माध्यम से राजस्व में वृद्धि और बेहतर अड्डे

- मोदी सरकार ने निवेश, दक्षता और डिलीवरी में सुधार लाने के लिए तीन हवाई अड्डों- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अहमदाबाद, लखनऊ और मेंगलूरू को पीपीपी मॉडल के माध्यम से पट्टे पर देने का फैसला किया है।
- इससे एएआई को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा।

सबसे ऊंचा एटीसी टॉवर

- नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 सितंबर 2019 को भारत के सबसे ऊंचे वायु यातायात नियंत्रण टॉवर का उद्घाटन किया गया।

समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना

विवाहित मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत - तीन तलाक की रूढ़िवादी प्रथा हटी

- असुरक्षित विवाहित मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने तीन तलाक की रूढ़िवादी प्रथा हटा दी है।
- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत अब 'तीन तलाक' को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को 'तीन तलाक' बोलकर दिया गया तलाक अब से अमान्य और अवैध माना जाएगा।
- तीन तलाक अब से एक दंडनीय अपराध हो गया है जिसके तहत तीन साल तक की जेल की सजा होगी और इसके साथ ही जुर्माना भी देना होगा।

बाल अधिकारों का संरक्षण : मोदी सरकार ने (पॉक्सो) अधिनियम में संशोधन किया

- बाल यौन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत बालकों और बालिकाओं दोनों से ही जुड़े यौन अपराधों को शामिल किया गया है।
- पोक्सो से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक साल के अंदर देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
- बच्चों को अच्छी एवं बुरी नीयत से स्पर्श किए जाने के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से देश भर के स्कूलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 40,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019; ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का अनुमोदन

- इसमें भेदभाव की मनाही के साथ-साथ ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों को परिभाषित किया गया है।
- कोई भी सरकारी अथवा निजी निकाय रोजगार देने में किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है।
- विधेयक में उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की एक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

जनजातीय लोगों का कल्याण

- 150 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) मंजूर किए गए ताकि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता संपन्न शिक्षा प्रदान की जा सके।
- 55 विद्यालय पहले से कार्यरत।
- वन धन योजना - वन धन विकास केन्द्रों के माध्यम से पारंपरिक वन उत्पाद/सामग्रियों का मूल्यवर्द्धन; जनजातीय लोगों को कौशल उन्नयन तथा क्षमता सृजन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- नागालैंड, झारखंड तथा महाराष्ट्र के लिए 123 वीडीवीके ईकाईयों की मंजूरी।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

- इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में 48 प्रतिशत महिलाओं सहित दो लाख भारतीय मुस्लिम बगैर किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे।
- 50 प्रतिशत बालिकाओं सहित 5 करोड़ विद्यार्थियों को अगले पांच वर्षों में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाएंगी।
- देश भर में फैली तकरीबन 6 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का लगभग 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है।

वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करना
वेतन संहिता, 2019 : महिलाओं की समानता सुनिश्चित की गई

- ऐतिहासिक अधिनियम - इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त किया गया है और समकक्ष पुरुष कर्मियों के बराबर वेतन सुनिश्चित किया गया है।
- इसमें संगठित के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के लगभग 50 करोड़ कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन का वैधानिक संरक्षण और समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
- असंगठित क्षेत्र के कई कामगारों जैसे कृषि श्रमिकों, चित्रकारों, रेस्तरां एवं ढाबों में काम करने वाले व्यक्तियों और चौकीदारों, जो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर थे, को न्यूनतम वेतन का विधायी संरक्षण मिलेगा।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना, 2019:

- मोदी सरकार ने 'प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना, 2019' को मंजूरी दी है, ताकि छोटे व्यापारियों को 60 साल की आयु हो जाने के बाद 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जा सके।
- लगभग 3 करोड़ छोटे व्यापारी इस योजना से लाभान्वित होंगे।
- सभी दुकानदार, रिटेल या खुदरा व्यापारी और स्व-रोजगार करने वाले व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे।

ईएसआईसी के तहत अंशदान में कमी

- सरकार ने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही के लिए ईएसआई अधिनियम के तहत अंशदान की दर 6.5% से घटाकर 4% कर दी। इसका फायदा 3.6 करोड़ कर्मचारियों और 12.85 लाख नियोक्ताओं को होगा।

वित्तीय धोखाधड़ियों से गरीबों को संरक्षण प्रदान करना - अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019

- अधिनियम से देश में गैरकानूनी ढंग से धन जुटाने की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
- इसका उद्देश्य सुव्यवस्थित रूप से ली जाने वाली जमाराशि को छोड़ अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने की एक व्यापक व्यवस्था करना और जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करना है।

सभी का सशक्तिकरण

वंचितों तक विकास की पहुंच

- वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2021-22 तक की अवधि के दौरान 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान सौंपने का प्रस्ताव है।
- वर्ष 2022 यानी भारत की आजादी के 75वें वर्ष तक सरकार गांवों में रहने वाले प्रत्येक एकल परिवार के लिए एक बिजली कनेक्शन और एक स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन सुनिश्चित करेगी।
- जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल मुहैया कराया जाएगा।
- प्रत्येक स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) की एक महिला को 'मुद्रा लोन' के तहत 1 लाख रुपये तक का ऋण लेने की अनुमति होगी। सत्यापित जन धन खाते वाली प्रत्येक महिला एसएचजी सदस्य को 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत, 16,085 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया, 41 लाख लाभार्थियों को भर्ती किया गया और 10 करोड़ ई-कार्ड जारी किए गए।
- आयुष्मान भारत के तहत, देश में 20,700 से अधिक स्वास्थ्य एवं वेल्नेस सेंटर काम करने लगे हैं।

एक देश एक राशन कार्ड

- इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, चार राज्यों - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू की गई है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

- एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, पीएमयूवाई ने 100 दिनों के भीतर आठ करोड़ का लक्ष्य पूरा किया है। पिछले 100 दिनों में 80 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को जोड़ा गया है।
- 29.08.2019 तक, पांच किलोग्राम वाले कुल 17,39,054 रिफिलों की बिक्री हुई और पांच किलोग्राम रिफिल की मांग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 4,89,322 है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)

- 16,494 स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए।
- 11,750 व्यक्ति/युवा शहरी क्षेत्रों में आजीविका के लिए विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित और प्रमाणित किए गए; 8,000 से भी अधिक को प्लेसमेंट मिला।
- 8,183 लाभार्थियों को व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता दी गई।
- 49 आश्रयों का निर्माण किया गया और फिर उन्हें शहरी बेघर लोगों के लिए इस्तेमाल में लाना शुरू किया गया।
- 164.27 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता इस अवधि के दौरान राज्यों को जारी की गई।

किसानों की आमदनी दोगुनी करने की ओर ठोस कदम

'पीएम-किसान' स्कीम के दायरे में अब सभी किसानों को लाया गया

- मोदी सरकार ने 'पीएम-किसान' स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 3.44 करोड़ और किसानों को इसमें शामिल कर लिया है, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या 6.37 करोड़ हो गई है।
- 100 दिनों में किसान परिवारों के लिए प्रत्यक्ष लाभ के रूप में 8,955 करोड़ रुपये अंतरित किए गए, कुल राशि 20,520 करोड़ रुपये हुई।

अन्नदाताओं के सुरक्षित जीवन यापन के लिए पेंशन योजना

- पीएम किसान मान धन योजना के तहत प्रथम तीन वर्षों में 5 करोड़ लघु एवं सीमान्त किसानों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
- 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले किसानों को न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

40 एलएमटी चीनी का बफर स्टॉक

- 1674 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 01 अगस्त 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी का बफर स्टॉक तैयार करना।
- चीनी मिलों द्वारा किसानों के खाते में सीधे-सीधे धन जमा करने की योजना के तहत भुगतान।
- इससे किसानों के गन्ने की बकाया धनराशि के समय पर भुगतान और चीनी की कीमतों में स्थिरता लाने में आसानी होगी।
- इस निर्णय से गन्ने की बकाया धनराशि के निपटारे द्वारा सभी गन्ना उत्पादक राज्यों की चीनी मिलों को लाभ होगा।

अतिरिक्त भंडार की खपत के लिए चीनी निर्यात नीति

- इस वित्तीय वर्ष में लगभग 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाएगा।
- गन्ना सीजन 2019-20 के लिए चीनी मिलों को 10,448 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्यात सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुल अनुमानित व्यय लगभग 6,263 करोड़ रुपये है।
- सब्सिडी की राशि चीनी मिलों द्वारा किसानों के खाते में सीधे सीधे जमा कराई जाएगी, बाद में बकाया रहने पर मिल के खाते में धनराशि जमा कराई जाएगी।

जैव ईंधन:

- इथेनॉल का खरीद मूल्य बढ़ाया गया। इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उसकी अधिक कीमत तय की गई है।
- इससे गन्ना किसानों की बकाया राशि में कमी करने में मदद मिलेगी और गन्ना उत्पादक किसानों की कठिनाइयां कम होंगी।
- पेट्रोल में अधिक मात्रा में इथेनॉल मिश्रित करने के कई लाभ हैं, जैसे आयात पर निर्भरता में कमी, कृषि क्षेत्र को समर्थन, अधिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन, कम प्रदूषण और किसानों की अतिरिक्त आय।

खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृत, खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का उद्देश्य किसानों को लागत से 1.5 गुना भुगतान करना है।
- किसानों के लिए उत्पादन लागत पर भुगतान की सर्वाधिक दर बाजरा के लिए 85 प्रतिशत, उड़द के लिए 64 प्रतिशत और अरहर के लिए 60 प्रतिशत है।

पैर और मुंह की बीमारी और ब्रुसेलोसिस उन्मूलन मिशन

- प्रधानमंत्री 11 सितम्बर, 2019 को राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे।
- केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान
- 2019 से 2024 तक योजना की कुल लागत तक 12,652 करोड़ रुपये

जल सुरक्षा की ओर

जल शक्ति मंत्रालय का गठन

- जल से संबंधित मुद्दों के शीघ्र और व्यापक समाधान के लिए अपने घोषणा-पत्र में किये गये वायदे को पूरा करने के लिए, मोदी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया।
- जल प्रबंधन और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के बारे में अब आम चर्चा हो रही है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निरंतर प्रयास को जाता है।
- 01 जुलाई, 2019 को जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान-जल शक्ति अभियान शुरू किया गया। मॉनसून के मौसम में जल की कमी वाले जिलों और ब्लॉकों पर जोर देते हुए, नागरिकों की भागीदारी द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा।
- 15 अक्टूबर तक चयनित 1146 ग्रामीण ब्लॉकों में जल शक्ति अभियान से संबंधित 2.11 लाख कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य है। इनमें से, अब तक 1.57 लाख कार्य पूरे किये जा चुके हैं।
- मनरेगा योजना के तहत सभी पांच प्राथमिकताओं - जल संरक्षण, पारम्परिक जल स्रोतो के पुनरुद्धार, संरचनाओं का फिर से इस्तेमाल और संभरण, वाटरशेड विकास और सघन वन रोपण में जल शक्ति अभियान को महत्वपूर्ण समर्थन मिलता है।
- 30 अगस्त, 2019 तक 7.23 लाख प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम)/जल संरक्षण कार्यों (मनरेगा) को पूरा किया गया है।

हर घर जल' के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में पहल

जल संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए **जल शक्ति मंत्रालय का गठन**

जल प्रबंधन और सभी के लिए सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता आज सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन गया है

जल शक्ति अभियान - 1 जुलाई 2019 को जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जल **संचयन संरचनाओं के निर्माण और व्यापक संचार के माध्यम** से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है।

सुशासन

पारदर्शिता को बढ़ावा - भ्रष्टाचार समाप्त करना

- जनहित में वरिष्ठ अधिकारियों सहित 49 कर समाहर्ताओं को मौलिक नियम 56 (जे) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई।

बजट सत्र 2019 - अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने का गवाह

- संसद ने अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए : अनुच्छेद 370 की समाप्ति, जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन, तीन तलाक विधेयक, मोटर वाहन विधेयक।
- 17वीं लोक सभा के बजट सत्र के दौरान संसद में कुल 40 विधेयक पेश किए गए (लोक सभा में 33 और राज्य सभा में 07) लोक सभा ने 35 विधेयक; राज्य सभा ने 32 विधेयक पारित किए और 30 विधेयकों को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया।

- लोक सभा के गठन के बाद पहली बार एक/प्रभावी सत्र में दोनों सदनों द्वारा 30 विधेयकों को पारित करना एक रिकॉर्ड है।
- लोक सभा में लगभग 137% और राज्य सभा में लगभग 103% कामकाज हुआ।

58 बेकार कानूनों को रद्द (निरस्त) किया गया

- मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद, 1,000 से अधिक बेकार कानूनों को रद्द किया गया। 2019 में, 58 बेकार कानूनों को रद्द करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई।
- इनमें से कुछ ने लोगों का जीवन और व्यवसाय आसान बना दिया क्योंकि इनमें से कुछ कानून अप्रचलित हो चुके थे लेकिन लोगों को परेशान करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता था।

गरीब, समाज के सुविधाओं से वंचित लोगों को टेली-कानून कार्यक्रम के अंतर्गत कानूनी सहायता

- पैनल वकील के जरिये 115 आकांक्षापूर्ण जिलों में पंचायत स्तर पर स्थित 28060 सार्वजनिक सेवा केन्द्रों (सीएससी) में उपलब्ध वीडियो कान्फ्रेंस और टेलीफोन सुविधा से कानूनी सहायता।
- टेली-कानून कार्यक्रम के तहत महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानव तस्करी के शिकार, भूकम्प और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह लेने के हकदार हैं।
- अन्य लोग 30 रुपये प्रति परामर्श पर टेली-कानून सेवा का लाभ ले सकते हैं।

कानूनी तंत्र को मजबूत बनाना

- मोदी सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी।
- सरकार के इस कदम का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करना है।

भारत बाघों के लिए सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित प्राकृतिक वास बना

- महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत में 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई।
- 33% की बढ़ोतरी अब तक की दर्ज सबसे अधिक वृद्धि है।
- देश में 'संरक्षित क्षेत्रों' में वृद्धि। वर्ष 2019 में 860 से अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं जो 2014 में 692 थे।

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत असाधारण तरीके से छलांग लगाते हुए 52वें रैंक पर पहुंचा

- भारत 5 स्थान की छलांग लगाते हुए वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2019 में 52वें रैंक पर पहुंच गया।
- किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा 29 स्थानों की छलांग लगाकर 2015 के 81 से 2019 में 52 पर आ जाना सबसे लंबी छलांग है।

आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

गैर कानूनी गतिविधियां (निरोधक) संशोधन कानून ,2019

- यह कानून केन्द्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी नामजद करने और उसकी सम्पत्ति जब्त करने की इजाजत देता है।
- महानिदेशक (एनआईए) को एनआईए द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों में आतंकवाद से प्राप्त सम्पत्ति को जब्त करने / कब्जा करने का अधिकार है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून, संशोधन कानून 2019

- भारत के बाहर होने वाले आतंकवाद सम्बन्धी अपराध, जिनमें भारतीय सम्पत्ति/नागरिक पीड़ित हुए हैं, उनके लिए एनआईए को अपरदेशीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है
- नये अपराधों जैसे विस्फोटक पदार्थ, मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण/ बिक्री और साइबर आतंकवाद को एनआईए की अनुसूची में शामिल कर उसके अधिकार बढ़ाए गए हैं।

साइबर अपराध नियंत्रण

- हर प्रकार के साइबर अपराधों की सूचना के लिए जनता की मदद के लिए नागरिक केन्द्रित पहल राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) की शुरूआत की गई ताकि पुलिस थाने नहीं जाना पड़े।
- सम्बद्ध राज्यों /संघ शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां, कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए इस पोर्टल में की गई शिकायतों तक ऑनलाइन पहुंच सकती हैं।

आपदा प्रबंधन

- आपदा के अनुरूप अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना- प्रधानमंत्री 23 सितम्बर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन में सीडीआरआई की शुरूआत करेंगे।

सड़क सुरक्षा

मोदी सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 के जरिये सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की

- मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019, लागू हो गया, जिससे देश में एक प्रभावशाली, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस वर्ष 1 दिसम्बर से वह अपने सभी टोल प्लाजा में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल एकत्र करना अनिवार्य करे।

इलेक्ट्रिक गतिशीलता को प्रोत्साहन

- बिजली से चलने वाले वाहनों (ईवी) पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया ताकि उपभोक्ता बिजली के वाहन खरीदने में समर्थ हो सकें।
- ईवी के चार्जर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया ताकि ईवी के लिए किफायती आधारभूत ढांचा तैयार किया जा सके।
- स्थानीय प्राधिकारों द्वारा इलेक्ट्रिक बस किराये पर लेने पर उसे जीएसटी से छूट दी गई ताकि सार्वजनिक परिवहन के लिए ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके।
- बिजली से चलने वाले वाहन खरीदने के लिए जो ऋण लिया गया है उसके चुकाए गए ब्याज में 1.5 लाख रूपये की अतिरिक्त आय कर छूट दी गई। इससे ऋण की अवधि में उन करदाताओं को करीब 2.5 लाख रूपये का लाभ होगा जिन्होंने बिजली से चलने वाले वाहन खरीदने के लिए ऋण लिया है।

रेलवे को प्रोत्साहन - भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन

- मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बजट 2019 में रेलवे को देश के विकास का इंजन बनाने के लिए एक रोडमैप दिया गया है। इसके तहत 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- रेलवे ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड दर्ज किया - अप्रैल से अगस्त 2019 के बीच एक भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई।
- दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रूटों पर 2022-23 तक गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति।
- शीघ्र ही दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू होगी, 95 रेलगाड़ियों को उत्कृष्ट मापदंड के रूप में उन्नत किया गया।
- तीन नई लाइनों को मंजूरी दी गई।
- इलाहाबाद-पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच एक तीसरी लाइन, सहजनवा-डोहरीघाट (उत्तर प्रदेश) के बीच नई लाइन, वैभववाड़ी-कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के बीच नई लाइन।
- न्यू बोंगईगांव - अगथोरी (असम) लाइन का दोहरीकरण।
- गुणवत्तापूर्ण भोजन - लाइव किचन फीड से लिंक किये गये क्यूआर कोडों के साथ भोजन के पैकेट शुरू किए गए।
- स्वच्छ पेयजल - मंडीदीप, भोपाल में रेल नीर संयंत्र की शुरूआत।

प्रधानमंत्री कुसुम

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
- इस योजना का लक्ष्य है -

  - 10,000 मेगावॉट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर
    अथवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र;
  - 17.50 लाख स्टैन्ड अलोन सौर कृषि पम्प लगाना;
  - ग्रिड से जुड़े हुए 10 लाख कृषि पंपों का सौर ऊर्जा में परिवर्तन
  - भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 30 जून, 2019 तक

ऊर्जा संरक्षण

- पिछले 100 दिनों के दौरान, 80 लाख से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए, लगभग 91,000 एलईटी ट्यूबलाइट वितरित की गईं, बिजली की कम खपत करने वाले 33,500 पंखे वितरित किए गए।
- इन उपायों से एक वर्ष में 123 मिलियन यूनिट बिजली की बचत की

दिबांग पनबिजली परियोजना

- मंत्रिमंडल ने अरूणाचल प्रदेश में दिबांग पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी।
- यह भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है जिस पर अनुमानित लागत 28080 करोड़ रूपये आएगी।
- इससे 2880 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा और बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगी।

स्मार्ट सिटी मिशन

- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत में 609 करोड़ रूपये मूल्य की 88 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। 2,778 करोड़ रूपये मूल्य की 153 नई परियोजनाओं के लिए निविदाएं दे दी गई हैं, 4,086 करोड़ रूपये मूल्य के 127 कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं।
- एक शहर एक प्रभाव, 100 दिन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। 100 स्मार्ट शहरों में से प्रत्येक ने 100 दिन में एक पहल का प्रस्ताव रखा है जिसे 2 अक्टूबर, 2019 को पूरा कर लिया जाएगा। इस पहल के तहत 2.7 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 तक 23,400 करोड़ रूपये के निवेश और केन्द्रीय सहायता से 4.26 लाख मकानों का निर्माण कराया जायेगा।
- ग्रामीण इलाकों में पात्र लाभार्थियों के लिए 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण कराया जायेगा।

किफायती आवास

- मकान खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज की अदायगी पर 2 लाख रुपये तक की छूट दी गई है यदि अपने कब्जे वाली सम्पत्ति है।
- 31 मार्च 2020 तक 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज की अदायगी पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट दी गई है।

- अतः, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार घर खरीद रहा है तो उसे अब ब्याज में 3.5 लाख रुपये तक बढ़ी हुई छूट का लाभ मिलेगा। इससे घर खरीदने वाले मध्यम वर्गीय परिवार को 15 वर्ष की ऋण की अवधि में करीब 7 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
- सस्ते घर बनाने वालों द्वारा अर्जित लाभ पर उन्हें एक टैक्स हॉलीडे की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है।

अंतर्देशीय जलमार्ग

- पहली बार, भारतीय जलमार्ग का इस्तेमाल दो देशों भूटान और बांग्लादेश के बीच जहाज में लदे माल (कार्गो) को लाने-ले जाने के लिए किया गया, पारगमन के लिए भारत का इस्तेमाल 12.07.19 को किया गया।
- भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने अपने समुद्री यात्री को बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ बायोमैट्रिक समुद्री यात्री पहचान दस्तावेज प्रदान किया।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का एक जहाज भूटान से 1000 टन माल लेकर राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) पर बांग्लादेश गया और भारत-बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग को नौवहन मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने डिजिटल तरीके से शुरू किया।
- भारत के प्रधानमंत्री की 8 जून, 2019 को मालदीव यात्रा के दौरान समुद्र के रास्ते यात्री और माल सेवा की स्थापना के लिए मालदीव के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे मालदीव और केरल के बीच बड़ी नौकाएं शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

पर्यटन

- ऐतिहासिक कुतुब मीनार और सफदरजंग के मकबरे की प्रकाश से सजावट की शुरूआत हुई।
- देश भर के 10 ऐतिहासिक स्मारकों को आम जनता के लिए रात 9 बजे तक खुला रखा जाएगा।
- अतुल्य भारत अभियान ने पाटा (पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन) स्वर्ण पुरस्कार 2019 जीता।
- साहसी पर्यटन- चार राज्यों की 137 पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए विदेशियों के लिए खोला गया।
- 'आदि महोत्सव' नवगठित संघ शासित प्रदेश लेह में 17 अगस्त को आयोजित किया गया- 20 से अधिक राज्यों के 160 आदिवासी शिल्पकारों ने अपनी उत्कृष्ट कृतियों का प्रदर्शन किया।
- टाइम पत्रिका की ओर से 2019 में विश्व के महानतम स्थानों को लेकर जारी सूची में गुजरात की 597 फुट ऊंची सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को जगह मिली है

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान का प्रारम्भ (एवाईडीएमएस)

- योग का संदेश फैलाने में मीडिया के योगदान के लिए तीन श्रेणियों में 33 सम्मान दिए जाएंगे।
- समाचारपत्रों में योग की सर्वश्रेष्ठ कवरेज की श्रेणी के अंतर्गत ग्यारह सम्मान 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में दिए जाएंगे।
- टेलीविजन में योग की सर्वश्रेष्ठ कवरेज की श्रेणी के अंतर्गत ग्यारह सम्मान 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में दिए जाएंगे।
- रेडियो में योग की सर्वश्रेष्ठ कवरेज की श्रेणी के अंतर्गत ग्यारह सम्मान 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में दिए जाएंगे।

सरकार का देश की रक्षा में लगे लोगों को समर्पित पहला फैसला

सरकार का देश की रक्षा में लगे लोगों को समर्पित पहला फैसला

- मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला निर्णय उसकी प्राथमिकताएं कहां है उसे दर्शाता है- उन लोगों के प्रति जो हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं।
- राष्ट्रीय रक्षा निधि के अंतर्गत 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में बड़े बदलाव स्वीकृत। छात्रवृत्ति की दर में पर्याप्त बढ़ोतरी।
- इसके अलावा छात्रवृत्ति का दायरा बढ़ाकर उसके अंतर्गत आतंकी हमलों या नक्सल हमलों के दौरान शहीद राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी लाया गया।

उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर ध्यान

मेडिकल शिक्षा की कायापलट करने के उद्देश्य से मोदी सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद कानून 2019 लाई

- राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद कानून का लक्ष्य छात्रों पर बोझ कम करना, चिकित्सा शिक्षा खर्च कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, भारत में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच बनाना है।
- इस कदम से देश में चिकित्सा शिक्षा के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
- इसी प्रकार, शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में एक वर्ष में सरकारी कॉलेजों में बड़े पैमाने पर मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी हुई। 25 नये सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2,750 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई।

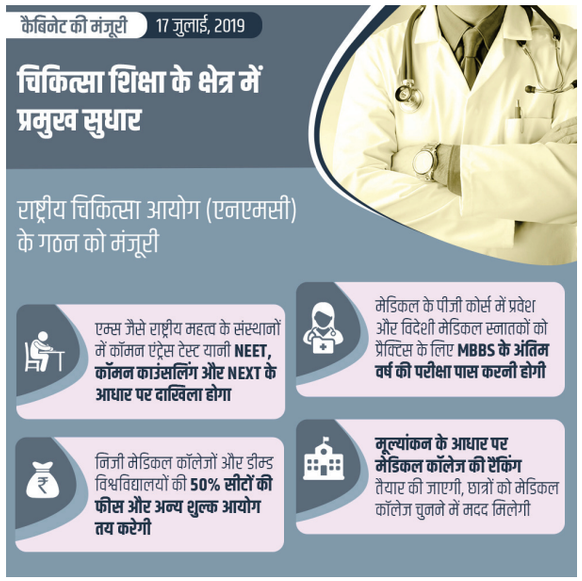

75 नये मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी

- केन्द्र प्रायोजित वर्तमान योजना के चरण-3 के तहत 75 अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई जिन्हें 2021-22 तक स्थापित किया जाएगा और वर्तमान जिला/ रैफरल अस्पतालों से जोड़ा जाएगा।
- इससे देश में एमबीबीएस की कम से कम 15,700 सीटें बढ़ेंगी, सरकारी क्षेत्र में विशेष तरह की चिकित्सकीय देखभाल में सुधार होगा, जिला अस्पतालों की वर्तमान सुविधाओं का इस्तेमाल हो सकेगा और देश में सस्ती मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- नये मेडिकल कॉलेज उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हैं।
- आकांक्षापूर्ण जिलों और 300 बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) कानून, 2019

- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक संवर्ग की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान
- इस निर्णय से अजा/अजजा/एसईबीसी/ई डब्ल्यूएस श्रेणियों के सभी प्रतिभाशाली पात्र उम्मीदवारों को आकर्षित कर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन मानकों में सुधार आएगा।

उच्चा शिक्षा को पहुंच योग्य बनाना/ आंध्र प्रदेश में 2 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय

- लोकसभा द्वारा पारित केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 में आंध्र प्रदेश में 2 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था है - आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय।
-

खेलों को बढ़ावा

- युवाओं में रोमांचकारी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नई दिल्ली स्थित इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एवरेस्ट मैसिफ अभियान और क्लाइम्बथन 2019 का आयोजन कर रहा है।
- भारत को उच्च शिक्षा का केन्द्र बनाने के लिए सरकार ने 'स्टडी इन इंडिया' का प्रस्ताव रखा है, ताकि विदेशी छात्र पढ़ाई करने भारत आ सकें।
- देश में समग्र अनुसंधान ईको-प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) का गठन किया जाएगा, सभी मंत्रालयों के तहत समेकित निधियां उपलब्ध

खेल

जम्मू और कश्मीर में डीडी के मुफ्त डिश सेट टॉप बॉक्स वितरण की शुरूआत

- डीडी कशीर से आधे घंटे के डोगरी कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन के साथ चैनल की सिग्नेचर ट्यून की भी शुरूआत।

जीवन कौशल- छात्रों को रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से सुधार के लिए जीवन कौशल कार्यक्रम की शुरूआत।

मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा की शुरूआत की- ताकि 42 लाख सरकारी शिक्षक तैयार किए जा सकें।

फिट इंडिया अभियान

- राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया अभियान की शुरूआत की।
- इसका उद्देश्य भारतीयों को फिटनेस प्रतियोगिताओं /गतिविधियों में शामिल होने और उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर फिटनेस को उनके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। .
- इस अभियान में फिटनेस और स्वस्थ जीवन से जुड़े सभी पहलुओं जैसे शारीरिक फिटनेस, मानसिक फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली, खाने की स्वस्थ आदतों, स्वास्थ्य और संतुलित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐहतियाती कदम, सतत और पर्यावरण अनुकूल जीवन आदि को शामिल किया गया है।

खोज के सिरे पर

चन्द्रयान 2

- भारत ऐसा पहला देश है, जिसने चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की है।
- भले ही चन्द्रयान-2 के लैंडर विक्रम का संपर्क चन्द्रमा की सतह से 2.1 कि.मी. पहले ही इसरो मुख्यालय के कन्ट्रोल सेन्टर से टूट गया, लेकिन इसका ऑर्बिटर अपने सिग्नल भेजता रहेगा।
- इस घटनाक्रम के साक्षी रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बैंगलुरू स्थित इसरो मुख्यालय में वैज्ञानिकों के साथ मौजूद थे।
-

- इस मौके पर उन्होंने कहा कि 'हमें देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है उन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। वैज्ञानिकों ने भारत को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। ये पल साहस वाले थे और हम आगे भी साहस दिखायेंगे। देश आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। आपका प्रयास सराहनीय है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि चन्द्रयान-2 के मिशन से हमें दो बड़ी सीख मिली है कि हमें अपना काम विश्वास और निडरता के साथ करना चाहिए।'

सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र

Earth as viewed by Chandrayaan-2 LI4 Camera on 03 Aug 2019 17:28 UT

Satellite Altitude: ~ 5000 km

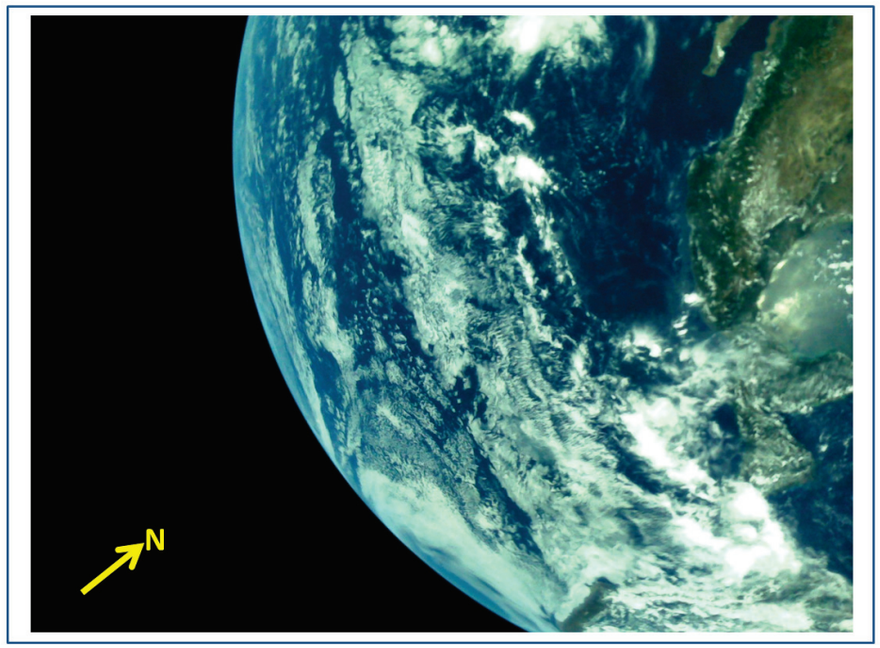

रक्षा सेनाओं के बीच तालमेल में मजबूती :

- सबसे बड़े सैनिक सुधार करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में घोषणा की कि देश में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस होगा। इससे बेहतर तालमेल ओर सशस्त्र सेना को और अधिक प्रभावशाली बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अपाचे हेलिकॉप्टर शामिल

- भारतीय वायु सेना में आठ एएच-64ई अपाचे हमलावर हेलिकॉप्टरों को 3 सितम्बर, 2019 को वायु सेना स्टेशन पठानकोट की सूची में शामिल किया गया। अपाचे हमलावर हेलिकॉप्टर एमआई-35 फ्लीट का स्थान लेंगे।

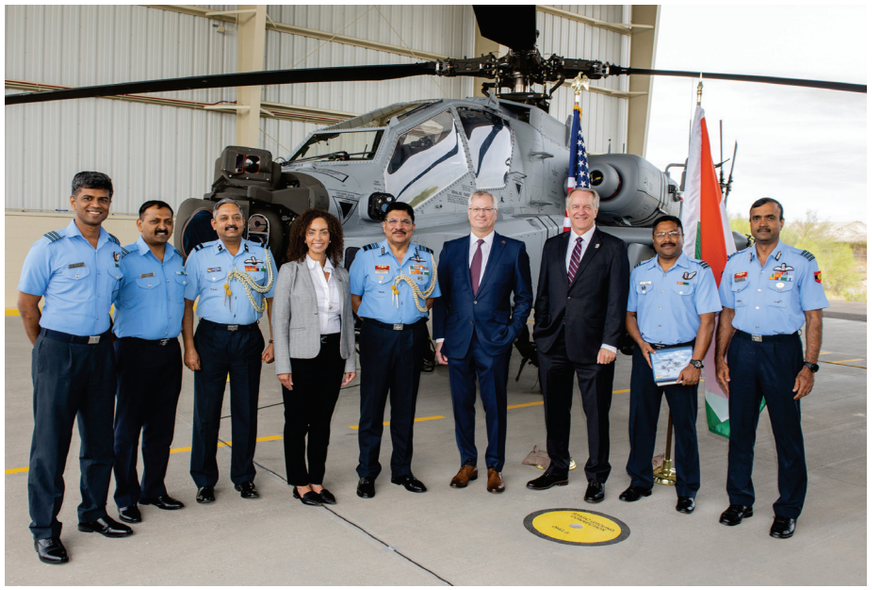

रक्षा-प्रौद्योगिकी का विकास और रक्षा कर्मियों का कल्याण

- रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 4 अगस्त, 2019 को चांदीपुर के परीक्षण समेकित स्थल (आईटीआर) से प्रत्यक्ष हवाई लक्ष्य को भेदने के लिए सतह से हवा में त्वरित प्रतिक्रिया से मार करने वाले आधुनिक प्रक्षेपास्त्र (क्यूआरएसएएम) का सफल हवाई परीक्षण किया।
- शांति क्षेत्र में तैनात तीनों सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए 18 जून, 2019 को उपभोग सामग्री के रूप में राशन की बहाली की गई। अब शांति क्षेत्र तैनात अधिकारियों सहित सशस्त्र सेना के सभी अधिकारियों को राशन मिलेगा।

बहादुर सीएपीएफ कर्मियों के लिए बड़े लाभ

- मोदी सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के अधिकारियों को संगठित संवर्ग दर्जा प्रदान किया है। इस कदम से वह नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (एनएफएफयू) सहित अनेक लाभ पाने के हकदार हो गए हैं।
- इस कदम से पांच प्रमुख सीएपीएफ या अर्धसैनिक बलों - सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी से हजारों सेवारत और 2006 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों को लाभ मिलेगा।

रेलवे सुरक्षा बल को संगठित समूह 'ए' का दर्जा

- रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को संगठित समूह 'ए' का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी।
- आरपीएफ को संगठित समूह 'ए' का दर्जा देने से पात्र अधिकारियों के करियर में प्रगति की स्थिति में सुधार होगा।

मोदी सरकार के कार्य की दुनिया में प्रशंसा

दुनिया का कहना है भारत दिन पर दिन स्वच्छ हो रहा है!

- यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार मोदी सरकार की स्वच्छ भारत पहल के कारण भूजल का प्रदूषण कम हुआ है और भारत के अनेक हिस्से खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो गए हैं।
- अध्ययन में कहा गया है कि स्वच्छ भारत का प्रभाव यह है : वर्ष 2000 और 2014 के बीच खुले में शौच में लगभग 3 प्रतिशत बिंदु प्रतिवर्ष की दर से कमी आई है, जबकि 2015-2019 से प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत बिंदु से अधिक की कमी दर्ज की गई है!

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - व्यापक असर वाला जन आंदोलन

- जन्म के समय अखिल भारतीय लिंग औसत बिंदुवार बढ़ा है- 2015-16 में प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 923 से बढ़कर मार्च, 2019 तक प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 931 हुई।
- हरियाणा में सुधार दर्ज किया गया - 2015-16 में प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 887 से बढ़कर 2018-19 में 914 हुई।

विश्व ने मोदी सरकार के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम को सराहा

- मोदी सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का प्रभाव यह है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बेहतर सड़क सम्पर्क के कारण खेती से खेतिहर मजदूरी में बदलाव आया है और अपने खेतों की देखभाल के लिए महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सराहना करते हुए कहा गया है कि इससे गतिशीलता बढ़ी है, आर्थिक अवसरों तक पहुंच बढ़ी है और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया है।
- इसमें यह भी कहा गया है कि घरों में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या में गिरावट आई है, यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है।

डीडी डिश पर बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के चैनल मुफ्त

- बांग्लादेश टेलीविजन का चैनल, बीटीवी वर्ल्ड, और दक्षिण कोरिया गणराज्य की सरकार का 24 घंटे का अंग्रेजी चैनल केबीएस वर्ल्ड दूरदर्शन फ्री डिश पर दिखाई देगा।
- डीडी इंडिया बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया में उपलब्ध होगा।
- इस फैसले से इन दोनों देशों के साथ भारत के सम्बन्ध मजबूत बनाने की ऐतिहासिक घटना होगी।

विश्व में भारत का कद बढ़ा

विश्व ने किया प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच सम्बन्धों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए यूएई का प्रतिष्ठित सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' प्रदान किया गया।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बहरीन के सुलतान किंग हमद ने 'आर्डर ऑफ रेनेसां ' प्रदान किया।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को द्विपक्षीय विशेष और विशेषाधिकृत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ सेंट एन्ड्रयू द अपोसल' दिया गया।

दुनिया भारत के साथ खड़ी है

- अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जी7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और दुनिया के नेता ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका, रूस भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के भारत के फैसले पर उसके साथ खड़े हैं। ये सभी प्रमुख शक्तियां सर्वसम्मति से भारत के कदम और ऐसा करने के उसके स्वतंत्र अधिकार का समर्थन कर रही

मरुस्थलीकरण के खिलाफ भारत ने COP-14 की मेज़बानी की।

भारत ने आगामी दो वर्षों के लिए COP प्रेसिडेंसी चाइना से ली।

भारत के नेतृत्व में वैश्विक गाथा

योग दिवस- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रेरक शक्ति का प्रभाव दिखाया

- पिछले कुछ वर्षो के समान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अति उत्साह के साथ दुनिया भर के 170 से अधिक देशों में मनाया गया। भारत को इससे वैश्विक स्तर पर अपना सांस्कृतिक प्रभाव दिखाने का लाभ मिला।
- इस बार, प्रधानमंत्री मोदी ने योग के प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान देने के लिए योग-2019 के लिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की।
- चार पुरस्कार विजेताओ में एक इटली की महिला और जापान का एक सांस्कृतिक

भारत और मालदीव की मित्रता में मिसाल देने योग्य बदलाव

- सरकार गठन के मात्र एक माह के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पड़ोसी देश में जोरदार नीतिगत विजय प्राप्त की।
- उनकी मालदीव यात्रा, शानदार स्वागत और इसके बाद का घटनाक्रम दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी यूपीए की बड़ी नीतिगत गलतियों को सुधार रहे हैं।
- मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया।

जरूरत के समय, पड़ोसी के साथ

विदेश नीति के प्रति पड़ोसी देशों को अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर के दिन हुए भयंकर आतंकी हमलों के बाद श्रीलंका की यात्रा करने वाले पहले विश्व नेता बने।

एससीओ शिखर सम्मेलन में वर्णित योजना

- प्रधानमंत्री मोदी ने आंतकवाद के खिलाफ अपनी बात रखकर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रभाव छोड़ा और इस पर विश्व भर में आम सहमति बनाने का आग्रह किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने बिसकेक में एससीओ शिखर सम्मेलन में किसी देश द्वारा समर्थित आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि आतंकवाद को समर्थन, सहायता और उसके लिए मदद देने वाले देशों को जवाबदेह बनाया जाए, साथ ही उन्होंने इस बुराई से निपटने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन और विदेश नीति

- प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक नेताओं और एससीओ अध्यक्ष को आमंत्रित किया।
- मालदीव की ऐतिहासिक यात्रा : प्रधानमंत्री मोदी ने मजलिस को संबोधित किया, विदेशियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द ऑर्डर ऑफ निशान इज्जुद्दीन ग्रहण किया।

स्वदेश में, प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का स्वागत किया, और व्यापार, आतंक और अन्य मुद्दों पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया।

जापान में जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के शीर्ष नेताओं से विस्तृत बातचीत की।

योग दिवस 21 जून को विश्व भर में बेहद उत्साह के साथ मनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत के पक्ष में निर्णय सुनाया।

जी 20 में प्रधानमंत्री मोदी- विस्तृत पहुंच, भविष्य के परिणाम

कार्य की सीमा

- प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 के चार सत्रों में हिस्सा लिया, 9 द्विपक्षीय बैठकें की, 8 व्यक्तिगत बातचीत की, 2 त्रिपक्षीय बैठकें (जापान-भारत-अमेरिका और रूस-भारत-चीन) की तथा ब्रिक्स के नेताओं के साथ एक बैठक में भाग लिया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में विश्व के सभी नेताओं के साथ शीर्ष द्विपक्षीय और व्यक्तिगत बैठकें की। यह विश्व मंच पर भारत के उदय का संकेत है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कोबे में विशाल सामुदायिक समारोह में भी भागीदारी की।

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ दो दिन में पच्चीस कार्यक्रमों में भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए मुद्दे विश्व में गुंजायमान रहे

- प्रधानमंत्री मोदी ने जी 20 शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य पर सत्र के दौरान भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों और विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत पर अपने विचार रखे।
- उन्होंने आपदा प्रबंधन पर संयुक्त वैश्विक प्रयास करने का आह्वान किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने लैंगिक समानता की आवश्यकता पर जोर दिया, प्रौद्योगिकी पर अपने विचार रखे और मनुष्य के विकास के लिए समाज से प्रौद्योगिकी अपनाने को सुनिश्चित करने को कहा।
- जी20 शिखर सम्मेलन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने भगौड़े आर्थिक अपराधियो के विरूद्ध संयुक्त रूप से कड़ी कार्यवाही करने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया।
- वर्ष 2014 से 2019 तक यह स्पष्ट हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी भष्ट्राचार मुक्त विश्व बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कुछ ईमानदार करदाताओं और ईमानदार व्यापारी की रक्षा की जा सके।
- प्रधानमंत्री मोदी भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ओसाका ट्रैक बातचीत में शामिल नहीं हुए। आंकड़ों के मुफ्त प्रभाव पर ओसाका ट्रैक और ई कामर्स ओसाका जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री आबे का प्रमुख मुद्दा था।

प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जोरदार आवाज उठाई

- चाहे जी 20, ब्रिक्स अथवा एससीओ शिखर सम्मेलन हो, प्रधानमंत्री मोदी ने आंतकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर राय बनाने में अहम भूमिका निभाई। ओसाका जी 20 शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने अपने विचार जोरदार तरीके से रखे।
- प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से आतंकवाद के मुद्दे पर सम्मेलन बुलाने की पहल करने और उन्हें पूरा सहयोग देने की बात की।

भारत और अमेरिका के मजबूत संबंध

- प्रधानमंत्री मोदी की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक को लेकर मीडिया में काफी उत्सुकता थी
- प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विविपक्षीय बैठक सरल और सफल रही। बैठक के दौरान दोनो नेताओं के बीच 5जी, व्यापार, ईरान और सुरक्षा संबंधो जैसे विविध मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ।
- निर्धारित द्विविपक्षीय बैठक के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने विभिन्न सत्रों और जी-20 देशों के नेताओं के रात्रि भोज के दौरान लीडर्स लाउंज में कई बार अनौपचारिक लेकिन गर्मजोशी के साथ बातचीत की।
- जी-20 नेताओं के रात्रि भोज में शामिल नेताओं ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद व्यस्त रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन से बातचीत की तो दूसरी तरफ वह राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी वार्तालाप में मशगूल रहे।

सबसे पहले पड़ोसी नीति

हमारे विश्वसनीय मित्र और सहयोगी भूटान की यात्रा

- भारत की पड़ोसी सबसे पहले की नीति पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त में भूटान का दौरा किया ताकि भारत-भूटान सम्बन्धों को और मजबूत बनाया जा सके।
- प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे त्सरिंग ने नये क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया; अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- भारत-भूटान पनबिजली सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डा. लोटे ने संयुक्त रूप से भूटान में 720 मेगावॉट की मंगदेचू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया।
- अंतरिक्ष सहयोग की नई ऊंचाइयों को छूते हुए, थिम्फू में दक्षिण एशिया उपग्रह भू स्टेशन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। टेली-मेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा, मौसम की भविष्यवाणी और प्राकृतिक आपदा की चेतावनी के लाभ भूटान के सुदूरवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों तक पहुंचेंगे।
- भूटान में भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के विस्तार का संयुक्त उद्घाटन किया गया। यह दोनों देशों के संस्थानों के बीच निकट सहयोग स्थापित करेगा।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान में रूपे कार्ड की शुरूआत की। इससे डिजीटल भुगतान, और व्यापार तथा पर्यटन में हमारे संबंधों में और सुधार होगा।

श्रीलंका यात्रा

- प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र से लगे अपने महत्वपूर्ण पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाई। ईस्टर के दिन बम हमले का शिकार सेंट एंटनी धर्मस्थल जाने वाले वह दुनिया के पहले नेता हैं।
- प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के नेतृत्व - राष्ट्रपति सीरीसेना, प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे, पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे और तमिल दलों के साथ पूरे जोश से बातचीत की।

वृहत्तर पड़ोस तक के संबधों को मजबूती

दुनिया में भारत के प्रभाव का बढ़ता दायरा

प्रधानमंत्री की यूएई यात्राः द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा

- यूएई में रूपे कार्ड की शुरुआत। खाड़ी का यह पहला देश जहां भारतीय रूपे कार्ड की शुरूआत की गई।

प्रधानमंत्री की बहरीन यात्राः किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा

- संस्कृति, अंतरिक्ष, आईएसए के साथ सहयोग और रूपे कार्ड के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर।
- बहरीन नेशनल स्टेडियम में उत्साही भारतीय समुदाय को संबोधित किया
- प्रधानमंत्री मोदी ने मनामा, बहरीन में श्रीनाथजी के 200 वर्ष पुराने मंदिर के दोबारा निर्माण की परियोजना की शुरूआत की।
- दया और इंसानियत दिखाते हुए, बहरीन सरकार ने उनके देश में सजा काट रहे 250 भारतीयों को माफ कर दिया।

प्रधानमंत्री की फ्रांस के साथ रणनीतिक सम्बन्धों को गहरा करने के लिए फ्रांस यात्रा

- प्रधानमंत्री भारत-फ्रांस सम्बन्धों को इन-फ्रा नाम दिया जिसका अर्थ है भारत फ्रांस मैत्री।
- फ्रांस और भारत ने द्विपक्षीय व्यापार, अंतरिक्ष, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाया।
- दोनों देशों ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के सहयोग के लिए चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण देने का फैसला किया। अंतरिक्ष यात्री 2022 तक भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा होंगे। प्रशिक्षण फ्रांस और भारत में दिया जाएगा।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत-फ्रांस सहयोग बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष जलवायु प्रभामंडल की शुरूआत की गई।

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA

Financial Express, Delhi
Saturday, 24th August 2019; Page: 16
Width: 66.46 cms; Height: 68.41 cms; a3; ID: 18.2019-08-24.152

Modi raises J&K in France: It took 70 yrs to remove word 'temporary'

SHUBHAJIT ROY
Paris, August 23

A DAY AFTER French President Emmanuel Macron said India and Pakistan should resolve the Kashmir issue bilaterally, Prime Minister Narendra Modi said on Friday that it took the country 70 years to remove the word "temporary". He was referring to the decision to revoke special status granted to Jammu and Kashmir (J&K) under Article 370, which, the government has said, was "temporary" in nature.

Addressing the Indian

"I am told that the Ganpati festival has become the main feature of the Parisian cultural calendar.

"On this day, Paris transforms into a mini-India. That is, a few days from now, the echo of 'Ganpati Bappa Morya' will also be heard here," he said.

On fighting terrorism, he said, "We have fought imperialism, fascism and extremism, not only in India but also on the soil of France. Our friendship is built on solid ideals. The character of the two countries is formed by the shared values of liberty

जी 7 शिखर सम्मेलन

भारत की सक्रिय भूमिका

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पानी की चिंता और महासागर प्रदूषण को कम करने के लिए भारत के योगदान पर प्रकाश डाला।
- प्रधानमंत्री ने डिजिटल बदलाव पर जी 7 शिखर सम्मेलन के समर्पित सत्र की अगुवाई की। उन्होंने सशक्तिकरण और समावेशन के जरिये सामाजिक असमानताओं से मुकाबला करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

अमरीकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत

- प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यारिज, फ्रांस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा और व्यापार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के बारे में विचार-विमर्श किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, एस और टी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने के बारे में बातचीत की।

रूस के साथ संबधों को मजबूती

मोदी व्लादीवोस्तक की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री - रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन और 5वें पूर्वी आर्थिक मंच में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए रूस की यात्रा की। रूस के सुदूर पूर्व व्लादीवोस्तक की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी।
- 20वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में, दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकृत रणनीतिक साझेदारी के आगे बढ़ने पर गौर किया।
- रूस ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनाने का पुरजोर समर्थन किया। रूस सुधारों से युक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन करता रहेगा।
- शिखर सम्मेलन के दौरान 2019-24 में हाइड्रोकार्बन में सहयोग के लिए रोडमैप पर हस्ताक्षर करने के साथ, दोनों पक्षों को अगले पांच वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की उम्मीद है।
- दोनों ने आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने के लिए सभी उपाय करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। रूस ने आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने के भारत के प्रस्ताव पर ध्यान दिया।

पूर्वोत्तर राज्यों का विकास

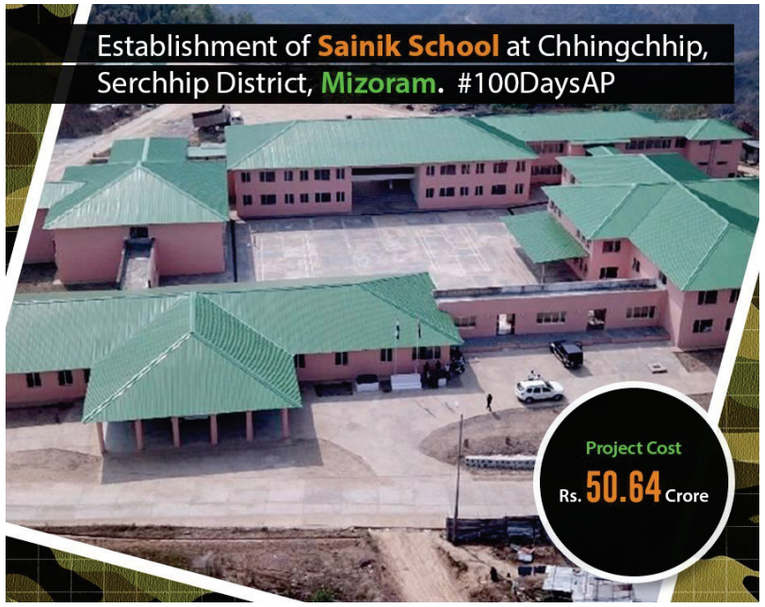
Establishment of Sainik School at Chhingchhip,
Serchhip District, Mizoram. #100DaysAP
Project Cost
Rs. 50.64 Crore

100 Day Action Plan
Target -
200 projects worth
about Rs. 3000 Crore
Implemented -
186 projects costing
Rs. 3024.04 Crore

Approval given for First Bamboo Industrial Park
to be set up in North East Region at Manderdisa
in Dima Hasao District of Assam in an area of
75 hectares and at a cost of Rs. 50 crores.
#100DaysAP

Bodoland Indigenous Tribal Art & Cultural Complex
cum Film Studio at Kathalguri, Kokrajhar. #100DaysAP
Project Cost
Rs. 4.95 Crore

मीडिया कवरेज

Live हिन्दुस्तान .com

22 अगस्त, 2019

विश्व के 100 महानतम स्थानों की सूची में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी'

टाइम पत्रिका की ओर से 2019 में विश्व के महानतम स्थानों को लेकर जारी दूसरी वार्षिक सूची में गुजरात की 597 फुट ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' और मुंबई के सोहो हाउस ने अपनी जगह बनाई है। यह सूची 100 नए और नए गौर करने लायक गंतव्य स्थानों का संकलन है, जिनका तत्काल अनुभव किया जाना चाहिए।

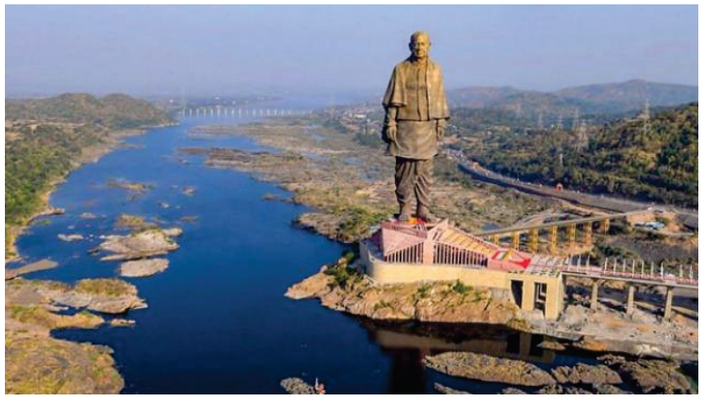

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो आजाद भारत के पहले गृह मंत्री के साथ ही उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि है। वहीं, मुंबई का फैशनेबल सोहो हाउस 11 मंजिला इमारत में स्थित है जहां से अरब सागर नजर आता है। इसमें एक पुस्तकालय, 34 सीटों वाला एक सिनेमाघर और खुली छत में बना एक बार और पुल हैं। इसके अलावा इस सूची में चाड का जोकुमा नेशनल पार्क, मिस्र की लाल सागर पर्वत श्रृंखला, वॉशिंगटन के न्यूजियम, न्यूयॉर्क सिटी के द शेड, आइसलैंड के जियोसी जियोथर्मल सी बाथ, भूटान के सिक्स सेंसेज होटल, मारा नोबोइशो कंजर्वेंसी के लेपर्ड हिल और हवाई के पोहोइकी को भी शामिल किया गया है।

जागरण

23 अगस्त, 2019

मजबूत इच्छाशक्ति से पीएम मोदी ने उठाया ऐसा कदम, जिसे कभी किसी सरकार ने सोचा तक नहीं

मोदी सरकार की कार्य पद्धति का मूल्यांकन करें तो ऐसे अनेक कदम नजर आएंगे जिन पर कभी किसी सरकार ने कदम उठाना दूर तक भी सोचा नहीं था।

आजादी के बाद हुए 17 लोकसभा चुनावों में देश ने 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। निःसंदेह इन सभी सरकारों ने राष्ट्र निर्माण में अपने विवेक के अनुसार कुछ न कुछ किया, परंतु ऐसी सरकारें विरली रहीं जो दूरगामी परिणाम लाने वाले काम कर सकीं। अपने 55 वर्षों के शासन में कांग्रेस को आठ बार पूर्ण बहुमत वाला जनादेश मिला, लेकिन उसने शायद दस काम भी ऐसे नहीं किए जिनसे देश को निर्णायक दिशा मिली हो।

हालांकि वाजपेयी सरकार ने अल्पकाल में कई बड़े काम करने के प्रयास किए, परंतु बहुमत के अभाव में उनका प्रभाव सीमित रहा। देश में पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में परिवर्तन की जो बयार बहती दिख रही है उसके पीछे मजबूत नेतृत्व और विकासोन्मुख नीतियां हैं।

सामान्य जन के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार

मोदी सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में ही दर्जनों ऐसे काम किए हैं जिनसे न केवल सामान्य जन के जीवन–स्तर में गुणात्मक सुधार आया है, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा भी विश्व में फिर से स्थापित हुई है। मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अतुलनीय दृढ़ इच्छाशक्ति है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण राज्यसभा में संख्याबल न होने के बावजूद अनुच्छेद-370 और 35-ए को समाप्त करना रहा। इन दोनों अनुच्छेदों के कारण कश्मीर देश की विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया जिससे वहां आतंकी और अलगाववादी शक्तियां फल-फूल रही थीं।

अनुच्छेद- 370/35-ए से मिली मुक्ति

आतंकी हिंसा से 41 हजार कश्मीरी मौत का शिकार हुए, केंद्र से भेजी जाने वाली विकास की राशि गिने-चुने लोगों की जेब

भरती रही और कई पीढ़ियां गरीबी और अशिक्षा का दंश झेलती रहीं। तुष्टीकरण की राजनीति और इच्छाशक्ति की कमी के कारण किसी भी नेता या सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद-370/35-ए से मुक्ति दिलाने का साहस नहीं किया। यह एक देश एक संविधान के सपने को पूरा करने की मोदी जी की मजबूत इच्छाशक्ति ही थी कि जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद-370/35-ए से मुक्ति मिल सकी।

सबसे मजबूत इच्छाशक्ति वाले प्रधानमंत्री

यह भी मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति ही है कि वह विषम राजनीतिक परिस्थितियों में

भी अनेक कठिन फैसले ले सके। कभी असंभव से दिखने वाले सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक जैसे फैसले लेना मोदी जी को देश का अब तक का सबसे मजबूत इच्छाशक्ति वाला प्रधानमंत्री साबित करता है। स्वतंत्रता के बाद देश की सरकारें अमीर-गरीब, शहर-गांव, कृषि-उद्योग जैसे अनेक विरोधाभासों से ग्रस्त रहीं। कुछ शक्तियों ने ऐसा वैचारिक वातावरण बना दिया था जिससे ये भ्रामक द्वंद्व देश के विकास में एक बड़ी बाधा बन गए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तत्काल इस द्वंद्व को खत्म किया। अमीर और गरीब की खाई पाट कर सबको एक साथ लेकर चलने की नीति प्रधानमंत्री मोदी के इस कथन से स्पष्ट होती है कि देश में सिर्फ दो वर्ग हैं, एक गरीब और दूसरा गरीबी हटाने वाला।

मोदी सरकार की प्राथमिकता

मोदी सरकार की नीतियों में गरीबों के कल्याण के प्रति चिंता और अन्त्योदय का भाव स्पष्ट नजर आता है। सामान्य जन के जीवन में बदलाव लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। जनधन, मुद्रा, सौभाग्य, स्वच्छ भारत, श्रमयोगी मानधन पेंशन, किसान पेंशन और लघु व्यापारी मानधन जैसी दर्जनों योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आमजन के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है।

सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाया

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें नीम कोटेड यूरिया लाना, समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना वृद्धि, समर्थन मूल्य दायरे का विस्तार, यूरिया सब्सिडी में वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि प्रमुख हैं। तीन तलाक उन्मूलन, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, मातृत्व अवकाश में वृद्धि जैसे निर्णयों के जरिये भी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। मोदी सरकार का मानना है कि व्यवसायी के विकास के बिना गरीबों का कल्याण संभव नहीं है।

सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था

मोदी जी ने वेल्थ क्रिएटर के महत्व को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है। चरमराई बैंकिंग प्रणाली के पुनरुत्थान, भ्रष्टाचार पर प्रहार के कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, कानूनों के सरलीकरण, जीएसटी इत्यादि जैसे अनेक प्रयास व्यापार को सुगम बना रहे हैं और भारत आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन कर पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। करदाताओं की संख्या और कर प्राप्ति में जिस तरह वृद्धि हुई है वह मोदी सरकार पर विश्वास और देश के विकास में भागीदारी का प्रतीक है।

विश्व पटल पर भारत की ऊंची होती साख

पाकिस्तान की आतंकी नीतियों का जवाब देने के लिए जब देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तब एक तरफ दुनिया के प्रभावी देश भारत के साथ थे तो वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क अलग-थलग पड़ा हुआ था। कश्मीर के मुद्दे पर भी स्थिति वही है। विश्व पटल पर भारत की ऊंची होती साख का एक और उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमारे सामने है। प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण के मुद्दे पर विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का नेतृत्व कर रहा है।

चंद्रयान ने देश का अंतर्राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया

चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण और एक बार में सर्वाधिक सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के

कीर्तिमान ने भी देश का अंतर्राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार की मंशा और नीति, दोनों स्पष्ट हैं। जहां सेना के आधुनिकीकरण का काम जारी है वहीं अंतरिक्ष में एंटी सेटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण से स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर यह सरकार जल, थल और नभ के साथ-साथ अंतरिक्ष तक जुटी हुई है। सेना के तीनों अंगों में समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने का फैसला भी ले लिया गया है। मोदी सरकार ने सैनिकों की वर्षों से लंबित ओआरओपी की मांग को भी पूरा करके उनके मनोबल को बढ़ाया।

सरकार के मूलभूत परिवर्तन लाने वाले साहसिक निर्णय

मोदी सरकार की कार्य पद्धति का बारीकी से मूल्यांकन करें तो ऐसे अनेक कदम नजर आएंगे, जिन पर कभी किसी सरकार ने कदम उठाना तो दूर, सोचा तक नहीं था। नरेंद्र मोदी ने सत्ता की परवाह किए बगैर देशहित को ध्यान में रखते हुए कठिन और मूलभूत परिवर्तन लाने वाले साहसिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो आमजन के हित में हों और जरूरी नहीं कि वह लोक लुभावने और देखने में अच्छे लगने वाले हों। इस सरकार ने सिद्ध किया है कि जब देशहित में कठिन निर्णय लिए जाते हैं तो जनता भी समर्थन देने में पीछे नहीं हटती। इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी का 2014 के जनादेश से बड़े जनादेश के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बनना है।

जागरण 17 अगस्त, 2019

वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को आइएसओ का मिला तमगा, जानिए कैसे हुआ कायाकल्प

पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और तमगा हासिल हुआ है। जी हां स्मार्ट सिटी की राह पर चल रहे वाराणसी शहर की रेल व्यवस्था में एक और सितारा जड़ गया है।

वाराणसी (राकेश श्रीवास्तव)। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और तमगा हासिल हुआ है। जी हां, स्मार्ट सिटी की राह पर चल रहे वाराणसी शहर की रेल व्यवस्था में एक और सितारा जड़ गया है। वाराणसी स्थित कैंट रेलवे स्टेशन को इस बार आइएसओ का तमगा मिला है। यह प्रमाणपत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए यहां हो रहे विशिष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। आइएसओ प्रमाणन की नई उपलब्धि मिलने से कैंट रेलवे स्टेशन प्रशासन अब खुशियां मना रहा है। इससे वाराणसी का यह प्रमुख रेलवे स्टेशन देश के चुनिंदा और बड़े रेलवे स्टेशनों में शामिल हो गया है जहां पर्यावरण की भी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है।

क्या हैं आइएसओ प्रमाण

आइएसओ (इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन) 14001:2015

पर्यावरण संरक्षण, यात्री सुविधा इत्यादि के लिए दिया जाता है। मानकों को पूरा करने के लिए कैंट रेलवे स्टेशन प्रशासन जमीनी स्तर पर प्रयास कर रहा था। अब प्रमाणन मिलने के बाद कैंट रेलवे स्टेशन को अन्य मानकों के लिए भी प्राथमिकता मिलनी तय हो गई है। इससे यह स्टेशन देश के शीर्ष रेलवे स्टेशनों में भी शामिल हो गया है जहां पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अतिरिक्त प्रयास हो रहा है।

क्यों मिली सफलता

कैंट रेलवे स्टेशन प्रशासन अपने उपयोग की कुल बिजली का 18 फीसद सौर ऊर्जा से पैदा कर खपत करता है। इसके

अलावा यहां धुलाई और नाले के गंदे पानी को री-साइकिल कर उसे दूसरी जरूरतों में खर्च करता है। कूड़े के निस्तारण, सफाई भी आइएसओ के मानकों को पूरा करने वाले साबित हुए। इसकी वजह से कूडा प्रबंधन के साथ ही जल प्रबंधन में भी परिसर नई नजीर सामने रख रहा है। अब वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के प्रयासों से दूसरे भी प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पहल करेंगे।

बोले अधिकारी

- 16 अगस्त 2022 तक के लिए यह प्रमाणपत्र मिला है। हम व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। एक-एक कर्मचारी, अधिकारी ने उपलब्धि दिलाने में सहयोग किया है।

-रवि चतुर्वेदी, अपर मंडल रेल प्रबंधक

- कैंट रेलवे स्टेशन पर नागरिक सुविधाओं के विस्तार के साथ ही विश्व स्तर की सेवाओं के लिए भी प्रशासन प्रयासरत है मगर पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और भी आगे ले जाया जाएगा ताकि यह दूसरों के लिए भी नजीर साबित हो।

-आनंद मोहन, स्टेशन निदेशक।

आज तक

22 अगस्त, 2019

PM मोदी के भूटान दौरे के पहले दिन हाइड्रो पॉवर समेत 9 करार, RuPay कार्ड भी लॉन्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में रुपे कार्ड लांच किया है। इसके साथ ही 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए।

भारत के बाद अब भूटान में भी रुपे कार्ड चलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय भूटान दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रुपे कार्ड लांच किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, 'दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और लोगों को एक साथ लाने के लिए मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग लोतेय ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड लांच किया। इससे दोनों देशों के नागरिकों को सुविधा होगी।'

इसके अलावा पीएम मोदी ने 9 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौते के तहत इसरो थिम्पू में अर्थ स्टेशन बनाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक बिजली खरीद समझौता भी हुआ। अन्य समझौते के तहत विमान हादसे और दुर्घटना की जांच, न्यायिक शिक्षा, अकादमिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विधिक शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एमओयू किए गए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से 720 मेगावाट के मांगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट का उद्घाटन किया। एक समझौते के

तहत थिम्पू में सैटकॉम नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। रवीश कुमार ने कहा कि मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से ग्राउंड अर्थ स्टेशन और सैटकॉम नेटवर्क का उद्घाटन किया। इसका निर्माण इसरो के सहयोग से किया गया है। इससे भूटान के सुदूर इलाकों में रहने वालों को काफी सुविधा होगी।

दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय आदान–प्रदान जारी है।'

बता दें कि भूटान यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हिमालयी राष्ट्र के महत्व को उनकी सरकार भली भांति जानती है। मौजूदा कार्यकाल के प्रारंभ में ही हो रही यह यात्रा भारत और भूटान के बीच ठोस

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थिम्पू पहुंचने पर भूटानी समकक्ष त्शेरिंग लोतेय ने उनकी अगवानी की। इसकी जानकारी देते हुए रवीश कुमार ने ट्वीट किया, 'हमारी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का केंद्रीय स्तंभ रहे भूटान के लिए प्रधानमंत्री मोदी की यह दूसरी यात्रा है और फिर से सरकार बनाने के बाद पहली यात्रा है।

संबंधों को रेखांकित करती है।

रंग ला रही है पीएम मोदी की कोशिश, ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में भारत ने बनाई टॉप 35 में जगह

रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ एशिया में ट्रैवल और टूरिज्म में बड़ी भूमिका निभाने वाला भारत देश वैश्विक स्तर पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

नई दिल्ली: सावर्जनिक मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील का प्रभाव पड़ने लगा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत को वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पेटिटिवनेस इंडेक्स में भारत ने 6 पायदान की छलांग लगाकर 34वें स्थान पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से टॉप 25 प्रतिशत देशों की तुलना में भारत ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पेटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40वें स्थान से 34वें पर पहुंच चुका है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ एशिया में ट्रैवल और टूरिज्म में बड़ी भूमिका निभाने वाला भारत देश वैश्विक स्तर पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादा आय वाली इकोनॉमी न होने के बावजूद चीन, मेक्सिको, मलेशिया और भारत ने टॉप 35 में जगह बनाई हुई है। इन देशों ने पारंपरिक संसाधनों और मजबूत मूल्य प्रतियोगात्मकता से यह जगह बनाई है।

वहीं, भारत ने इसमें सर्वाधिक उन्नति की है। बता दें कि 2015 में वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पेटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का 52वां स्थान था। वहीं, 2017 में यह 40वें स्थान पर था।

जन आवाज

जूली देवी, बेगूसराय, बिहार

पहले शौच के लिए खुले खेत में जाना पड़ता था। सब देखते थे, हम अस्वस्थ भी रहते थे लेकिन **'स्वच्छ भारत'** के तहत शौचालय बनने से हमने खुले में शौच करना छोड़ दिया और मेरे बच्चे भी अब बीमार नहीं पड़ते।

नरेश, यमुना नगर, हरियाणा

जैसे ही बरसात होती थी, पानी घर में भर जाता था। **'अमृत योजना'** से हमारा घर पक्का बनवाया गया और तब से बरसात के पानी से हमें छुटकारा मिला।

सकुना देवी, देवघर, झारखंड

खाना बड़े कष्ट से बनता था। लेकिन **'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना'** से खाना समय से बन जाता है और बच्चे भी समय से खा लेते हैं।

शमीम अन्सारी, रोहतास, बिहार

करीब 5 साल पहले बड़ी दुर्दशा थी यहां की। गाड़ी तो दूर की बात, पैदल चलना दुश्वार था। लेकिन **'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'** के तहत रोड बनने से बहुत सहूलियत हो गई है।